जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 353 प्रभात उदयपुर, रविवार 26 अक्टूबर, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

युवा नेताओं को जिलाध्यक्ष के रूप में पनपाने की योजना फेल हुई राजस्थान में

पुराने नेता, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा, सी.पी. जोशी व जूली संगठित हुए अपनी पकड़ बरकरार रखने के लिए

-रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- उनकी ''राय'' पर प्रभारी रंधावा अपनी मोहर लगा रहे हैं।
- कांग्रेस के नेताओं ने अध्यक्ष खड़गे व राहुल गांधी को इस मुतल्लिक ज्ञापन भी दिये हैं, किन्तु उनकी शिकायतें अनसुनी सी रह गई हैं।
- डोटासरा के उम्मीदवारों पुष्पेन्द्र भारद्वाज और सुनील शर्मा के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखे हैं, क्योंकि पुष्पेन्द्र भारद्वाज के खिलाफ कई मामले हैं और सुनील शर्मा, जिन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया था, का भारी विरोध होने के कारण खुद सोनिया गांधी ने टिकट काट दिया था।

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया, जो राहुल गांधी का विशेष रुप से प्रिय प्रोजैक्ट था, अब मज़ाक बन चुकी है। वरिष्ठ नेता अपने-अपने क्षेत्रों में अपने समर्थकों को जिलाध्यक्ष बनवाने की कोशिश में एकजुट हो गए हैं।

सभी पर्यवेक्षकों ने कल अपनी रिपोर्टें जमा कर दीं और अब अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व को लेना है। लेकिन इसी बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नामों का एक पैनल सौंप दिया है, जो पूरी तरह अनावश्यक और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रंधावा के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता एकजुट होकर चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

सी.पी. जोशी अपने क्षेत्र में अपने लोगों को जिलाध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, और जब भी किसी के नाम का प्रस्ताव रखा जाता है, सभी तुरंत हां में हां मिला देते हैं।

विधाक दल के नेता जूली को भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पुष्पेन्द्र भारद्वाज और सुनील शर्मा के खिलाफ पत्र लिखे हैं, जिन्हें डोटासरा ने उम्मीदवार बनाया है। भारद्वाज पर मुकदमे चल रहे हैं और कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं, सुनील शर्मा की जयपुर विधानसभा उम्मीदवारी पहले ही सोनिया गांधी ने रद्द कर दी थी, क्योंकि शशि थरूर ने उनके खिलाफ ट्वीट किया था। शर्मा ने दोनों गांधी नेताओं को ''तानाशाह'' कहा था।

राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, वह राहुल गांधी की उस मूल पहल की भावना के खिलाफ है, जिसका उद्देश्य जिलाध्यक्षों को सशक्त बनाना और योग्य व नई नेतृत्व क्षमता वाले लोगों को सामने लाना था, ताकि पार्टी को लाभ हो सके। लेकिन हो यह रहा है कि वही पुराने नेता अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए पहले से बदनाम और हार चुके चेहरों को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे नई नेतृत्व पंक्ति उभर नहीं पा रही।

और अगर एआईसीसी के प्रभारी महासचिव, इस मामले में रंधावा भी इसमें शामिल हैं, तो कार्यकर्ताओं के पास शिकायत करने या न्याय पाने का कोई रास्ता नहीं बचता।

राजस्थान में यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है, जब से अशोक गहलोत ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके महासचिवों को प्रभावित कर पार्टी पर मजबूत पकड़ बना ली थी। के.सी. वेणुगोपाल भी इस पूरी चाल में शामिल माने जा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि रंधावा के गहलोत, जोशी, डोटासरा और अन्य कई नेताओं से मजबूत संबंध हैं।

राहुल गांधी को अब अपनी आंखें खोलनी होंगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि इन राज्यों में चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो।

मुख्यमंत्री ने अकलेरा व श्रीगंगानगर मंडी के विकास कार्य को मंजूरी दी

जयपुर, 25 अक्टूबर। कृषि क्षेत्र में सुविधाओं एवं सेवाओं का विस्तार कर किसान कल्याण के लक्ष्य को साकार करने कें लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की अकलेरा एवं श्रीगंगानगर मंडी

- दोनों मंडियों में विकास के लिए 2.28 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।

में विकास कार्य के लिए 2 करोड़ 28 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

झालावाड़ जिले की कृषि उपज मंडी अकलेरा में ई-नाम हॉल के कार्यालय भवन सहित नवीन निर्माण कार्यो के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, कृषि उपज मंडी श्रीगंगानगर के फल-सब्जी व वन उपज मंडी यार्ड में विद्युत कार्यों के लिए भी लगभग 50 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 के तहत टोंक जिले में कृषि उपज मंडी टोडारायसिंह के प्रथम बोर्ड के गठन का अनुमोदन भी किया गया है। जिससे इस मंडी का प्रशासनिक संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

सीताराम केसरी भी बिहार चुनाव में मुद्दा बने

राहुल गांधी ने बिहार के बड़े नेताओं की स्मृति में प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसमें सीताराम केसरी का नाम भी शामिल था

- श्रीनंद झा -

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- मोदी ने पलटवार करते हुए कहा, बैकवर्ड नेता सीताराम केसरी का तिरस्कार किया था कांग्रेस ने, सम्मान नहीं। उन्हें बेरहमी से अध्यक्ष पद से हटाकर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया था। साथ ही कांग्रेस गठबंधन बंदोपाध्याय समिति की सिफारिशों को घोषणा पत्र का हिस्सा बनाना चाहता है।
- बंधोपाध्याय समिति का गठन नीतीश सरकार ने किया था। पर, उनकी सिफारिशें इतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव थीं कि उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। रिपोर्ट में बटाईदारों के हितों की सुरक्षा तथा लैंड होल्डिंग पर सीमा बाँधने की सिफारिश की थी। फॉरवर्ड-बैकवर्ड के संघर्ष के कारण नीतीश सरकार इसे लागू नहीं कर पा रही थी, इसे महागठबंधन अब लागू करना चाह रहा है।

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। चुनावी बिहार में पिछड़ा बनाम अगड़ा मुद्दा ज़ोर पकड़ रहा है। विपक्षी महागठबंधन कथित तौर पर भूमि सुधारों पर डी. बंद्योपाध्याय समिति की सिफारिशों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने पर विचार कर रहा है, जो 28 अक्टूबर को जारी होने की उम्मीद है। इसी बीच, ओबीसी बनिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दिवंगत कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी का नाम बिहार की चुनावी राजनीति में फिर से चर्चा में आ गया है।

कांग्रेस नेताओं, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल थे, ने बिहार के इस कद्दावर कांग्रेसी नेता केसरी को एक स्मृति सभा में श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि 1998 में केसरी को अपमानित करके कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। मोदी ने बेगुसराय में एक रैली में कहा, ''बिहार की जनता कांग्रेस को आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी।''

दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, एनडीए और महागठबंधन, ओबीसी और पिछड़े मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। इससे पहले, नरेन्द्र मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया था, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर की पोती को उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन के अंदर, भूमि सुधारों पर विवादास्पद बंदोपाध्याय समिति की सिफारिशों को लागू करने के वादे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की ज़ोरदार कोशिश चल रही है।

नीतीश कुमार द्वारा गठित बंदोपाध्याय समिति ने 2008 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। तथापि, सिफारिशों पर तीखी और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, नीतीश कुमार ने रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। समिति ने बटाईदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने और भूमि जोत की सीमा तय करने की भी सिफ़ारिश की थी। संयोग से, बंदोपाध्याय ने 1970 के दशक के अंत में ''ऑपरेशन बर्गा'' के तहत पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वामपंथी दल घोषणा पत्र में बंदोपाध्याय समिति की सिफारिशों को शामिल करने पर ज़ोर दे रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस और राजद नेताओं को आशंका है कि यह रणनीति उल्टी पड़ सकती है।

एलआईसी ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया

एलआईसी ने कहा, सारे निवेश पूरी तरह सोच-विचार कर और ईमानदारी से किए गए हैं

-जाल खंबाता -

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- एलआईसी ने वॉशिंगटन पोस्ट के इस आरोप को झूठा, निराधार व तथ्यों से परे बताया कि एलआईसी ने किसी दबाव में निवेश किया है।
- एलआईसी ने आरोप लगाया कि वॉशिंगटन पोस्ट ने एलआईसी की छवि और भारत में फायनैंशियल सैक्टर की मजबूत नींव को क्षति पहुँचाने की कोशिश की है।

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने शनिवार को ''द वॉशिंगटन पोस्ट'' द्वारा प्रकाशित झूठी रिपोर्ट्स का खंडन किया और पुनः पुष्टि की कि सभी निवेशों को ईमानदारी और उचित परिश्रम के साथ किया गया है।

''द वॉशिंगटन पोस्ट'' के एक लेख में दावा किया गया था कि अधिकारियों ने मई में एक प्रस्ताव को कथित तौर पर तेजी से मंजूरी दी, जिसके तहत एलआईसी से लगभग 3.9 बिलियन डॉलर का निवेश अडानी समूह की एक कंपनी में किया गया।

इस लेख का खंडन करते हुए, एलआईसी ने कहा कि ''द वॉशिंगटन पोस्ट'' द्वारा लगाए गए आरोप, कि एलआईसी के निवेश निर्णय बाहरी कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं, ''झूठे, निराधार और सत्य से दूर'' हैं

कंपनी ने एक बयान में कहा, ''लेख में आरोपित दस्तावेज़ या योजना कभी भी एलआईसी द्वारा तैयार नहीं की गई है, जो एलआईसी को अडानी समूह की कंपनियों में धन का निवेश करने का रोडमैप बनाती हो।''

लेख में दावा किया गया था कि अधिकारियों ने पिछले साल मई में एक प्रस्ताव को कथित तौर पर तेजी से मंजूरी दी, जिसके तहत एलआईसी से लगभग 3.9 बिलियन डॉलर का निवेश अडानी समूह की एक कंपनी में किया गया।

एलआईसी ने कहा कि निवेश निर्णय स्वतंत्र रूप से बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुसार किए जाते हैं, जिनमें गहन एवं आवश्यक परिश्रम (ड्यू डिलिजेंस) की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

कंपनी ने बयान में आगे कहा, ''इस तरह के निर्णयों में डिपार्टमैंट ऑफ फायनैंस सर्विसेज़ या अन्य किसी संस्था

(शेष पृष्ठ 4 पर)

दस से पन्द्रह राज्यों में अगले सप्ताह से एस.आई.आर. शुरु होगी

- जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। भारत का निर्वाचन आयोग अगले हफ्ते से देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) का पहला चरण शुरू कर सकता है। अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान ''10 से 15''

- इनमें असम, तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं।

राज्यों में एक साथ शुरु होगा, जिसमें वो राज्य भी शामिल हैं, जहाँ अगले साल चुनाव होने हैं।

असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे और ये उन राज्यों में शामिल हैं, जहाँ मतदाता सूची संशोधन का काम

(शेष पृष्ठ 4 पर)

'मई 2025 में एलआईसी ने अडानी समूह में 33,000 करोड़ रूपए लगाए थे'

वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि यह पैसा 30 करोड़ पॉलिसी धारकों की बचत का था

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर में बताया गया है कि उसके पास जो आंतरिक दस्तावेज हैं उनसे पता चला है कि सरकार के अधिकारियों ने एलआईसी द्वारा अडानी की कंपनी के 33,000 करोड़ रूपए का निवेश का प्रस्ताव तैयार किया था।
- अखबार कहता है कि इस निवेश का लक्ष्य है, अन्य निवेशकों को अडानी ग्रुप में निवेश के लिए प्रेरित करना।

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। हाल ही में मीडिया में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि मोदी-अडानी की सांठगांठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और इसके 30 करोड़ पॉलिसीधारकों की बचत का कैसे सोचे -समझे तरीके से दुरुपयोग किया। ''वॉशिंगटन पोस्ट'' ने इस घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि मोदी सरकार ने किस तरह अडानी एन्टरप्राइज़ेज़ की मदद की।

आंतरिक दस्तावेजों से पता चलता है कि भारतीय अधिकारियों ने मई 2025 में अडानी ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में एलआईसी फंड्स के 33,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया और इसे पारित किया। इसके उद्देश्य थे- ''अडानी ग्रुप में विश्वास का संकेत देना'' और ''अन्य निवेशकों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना।''

इस पूरे मोदी-अडानी मेगा घोटाले की जांच केवल एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जा सकती है, जिसकी माँग कांग्रेस पार्टी लगभग तीन वर्षों से कर रही है-जब से उसने अपनी 100 सवालों की श्रृंखला ''हम अडानी के हैं कौन'' (एचएएचके) प्रकाशित की थी।

पहला कदम यह होना चाहिए कि कम से कम संसद की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी (पीएसी) पूरी तरह से यह जांचे कि एलआईसी को वास्तव में अडानी ग्रुप में निवेश करने के लिए कैसे मजबूर किया गया। यह पीएसी के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से आता है।''

कांग्रेस के महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि सवाल यह उठता है कि किस दबाव में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि उनका काम एक निजी कंपनी को वित्तीय कठिनाइयों से उबारना था, जो गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण संकट में थी। उन्होंने इसे ''मोबाइल फोन बैंकिंग'' का मामला बताया।

जयराम रमेश ने कहा, जब सार्वजनिक पैसे को भ्रष्ट कंपनियों को दिया गया, तब यह स्पष्ट हुआ कि एलआईसी ने 21 सितंबर 2024 को केवल चार घंटे की ट्रेडिंग में 7850 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया, इसके

(शेष पृष्ठ 4 पर)

नियुक्ति के बाद चयन निरस्त करने पर रोक

जयपुर, 25 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु परिचर भर्ती-2023 में नियुक्ति देने के बाद अभ्यर्थी का चयन निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में प्रमुख पशुपालन सचिव और निदेशक सहित कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस

- हाई कोर्ट ने पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव, निदेशक तथा कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी किया।

जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने ये आदेश अशोक कुमार धाकड़ की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने अक्टूबर, 2023 में पशु

(शेष पृष्ठ 4 पर)

भारत में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेयर अर्थ की डिपॉज़िट्स हैं, पर आज भी ज़मीन का माल ज़मीन में ही क्यों रह गया है

कागज़ी कार्यवाही इतनी गलाघोंट है कि खनिज की डिस्कवरी और खान को प्रोडक्शन में आने में पंद्रह साल लग जाते हैं

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- पर, 2023 में कुछ आशा जगी, क्योंकि 1957 के माइंस एण्ड मिनरल्स एक्ट में सरकार को परिवर्तन करना पड़ा और प्राइवेट सैक्टर को भी रेयर अर्थ के खनिजों को खोद कर निकालने की सुविधा मुहैया कराई है।
- यह परिवर्तन इसलिए हुआ, क्योंकि सरकार को यह अहसास हो गया कि केवल सरकारी कॉर्पोरेशन को ही माइनिंग का अधिकार प्राप्त रहेगा तो मिनरल का एक्स्प्लॉयटेशन कभी पूरा नहीं हो पायेगा।
- चीन में जिस दिन मिनरल मिलता है, दूसरे दिन ही खुदाई शुरु हो जाती है। जब तक भारतीय खान मालिक पुरानी खान नीति के तहत परमिशन को ढूँढ रहा होता है, चीन का माल बाज़ार में आ चुका होता है।

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। भारत के पास खनिज हैं, लेकिन गति नहीं। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के भंडारों का मालिक होने के बावजूद, खोज को उत्पादन में बदलने में 15 साल तक का समय लग जाता है।

जब भारत कागजी कार्रवाई में लगा होता है तब चीन पृथ्वी की खुदाई करता है।

अदिति गुर्लीकर के इस गहन अध्ययन में, भूवैज्ञानिक और अन्वेषक चन्नमल्लिकार्जुन बी. पटिल यह बताते हैं कि कैसे नौकरशाही, ड्रिलिंग की सीमा कम करके और पुराने ढांचे के लिए खनिज संपदा को जमीन के बाहर आने से रोकते है।

एआई-संचालित अन्वेषण से लेकर खनन नीति में चुपचाप हो रहे परिवर्तन तक, यह कहानी उन टैक्टॉनिक बदलावों को उजागर करती है, जो भौगोलिक संपत्ति को राष्ट्रीय शक्ति में बदलने के लिए आवश्यक हैं।

भारत दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों के सबसे समृद्ध भंडारों में से एक है, फिर भी दशकों की नीति संबंधी निष्क्रियता, लालफीताशाही और सावधानी की गलत सोचने इस भौगोलिक खजाने को जमीन में ही बंद कर दिया है, जबकि चीन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है।

भारत के प्राचीन उपमहाद्वीपीय ढाल के नीचे एक भौगोलिक धरोहर है, जो देश को महत्वपूर्ण खनिज सुपरपावर के रूप में स्थापित कर सकती हैं। दुर्लभ पृथ्वी तत्व, लिथियम, निकल, टाइटेनियम (वह कच्चा माल जो पवन टरबाइन, लड़ाकू विमानों, और स्मार्टफोन बैटरियों से लेकर सभी चीजों को शक्ति प्रदान करता है) इस भूमि पर प्रचुर मात्रा में हैं, यह कभी गोंडवाना भूमि का हिस्सा थी, जो पैंजिया सुपरमहाद्वीप का दक्षिणी भाग था।

आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बयान करते हैं। भारत के पास लगभग 6.9 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ पृथ्वी के भंडार हैं, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर है। देश में लगभग 30 महत्वपूर्ण खनिज हैं, जिनमें से बड़े भंडार कर्नाटका के मंड्या जिले के लिथियम क्षेत्रों से लेकर केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के मोनाजाइट-समृद्ध तटीय रेतों तक फैले हुए हैं।

फिर भी, यह भौगोलिक संपत्ति अधिकांश रूप से उपयोग नहीं की गई है, जो तकनीकी कमियों और पुराने ढांचों के कारण बंद पड़ी है। हालांकि, 2023 के बाद के नीति परिवर्तनों ने एक नया युग शुरू किया है।

''चन्नमल्लिकार्जुन बी. पटिल, जो संस्थापक हैं, कहते हैं। भारत ने नक्शा बनाने और प्रारंभिक अन्वेषण के मामले में अद्भुत काम किया है,'' देश का लगभग 95-98 प्रतिशत क्षेत्र इस सम्बंध में कवर किया गया है, इसके लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल एक्सप्लोरेशन और कंसल्टेंसी लिमिटेड, और परमाणु खनिज निदेशालय जैसी संस्थाओं का धन्यवाद।''

यह आधारभूत कार्य भारत को खनिज विकास के अगले चरण में तेजी से प्रवेश करने की स्थिति में ला सकता है।

उन्होंने कहा, ''यह एक बहुत बुनियादी संकेतक है, और यह पर्याप्त डेटा प्रदान नहीं करता। दुनिया यह जानना चाहती है कि भारत के पास इन महत्वपूर्ण खनिजों में से वास्तव में

(शेष पृष्ठ 4 पर)

राजस्थान में 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले

जयपुर, 25 अक्टूबर। राज्य सरकार ने शनिवार देर रात एक आदेश जारी कर 67 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए। इनमें से 24 को

- इनमें से 24 को एसडीएम लगाया गया है।

एसडीएम लगाया गया है। तबादला सूची में उन आरएएस अफसरों का नाम भी है, जो दो दिन पहले ही पदोन्नत हुए थे।

आदेश के अनुसार गजेन्द्र सिंह राठौड़ को सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, भागचंद बधाल को जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त, दिनेश कुमार शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सचिव के पद पर लगाया गया है। गुंजन सोनी को संस्कृत विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, संजय कुमार माथुर को एडीएम तृतीय जयपुर, नरेन्द्र कुमार वर्मा को अतिरिक्त कलक्टर जयपुर पूर्व के पद पर लगाया गया है।